

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक / बैठक / 2009 / (गो/वि. प्र/अवका)/ 965-93 दिनांक : 30 अप्रैल, 2009

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की कार्यकारी समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 17 अप्रैल, 2009 का कार्यवाही विवरण

कार्यकारी समिति की द्वितीय बैठक श्री मोरव गोयल, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में 17 फरवरी, 2009 को अपरान्ह 3:00 बजे उनके कक्ष में आयोजित की गयी जिसमें उपस्थित सदस्यों व अन्य अधिकारियों का नाम संलग्न परिशिष्ट संख्या 1 में अंकित है। बैठक का एजेण्डा व उन में दिवें गये निर्णयों का विवरण निम्न अनुसार है-

प्रस्ताव संख्या 1 गत बैठक दिनांक 11 फरवरी, 2009 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि

गत बैठक दिनांक 11 फरवरी, 2009 के कार्यवाही विवरण का निम्न सशोधनों के साथ सर्व समाप्ति से अनुमोदन किया गया-

1- गत बैठक के प्रस्ताव संख्या 1 पुष्ट संख्या 3 पर मध्यम मन्चित्र समिति प्रथम एन द्वितीय के स्तर में एक जोड़ा आवक कि निर्देशना (आयोजना) का पट रिक्त रहने तक समिति के सदस्य सक्रिय रूप में निर्मोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर रहेंगे।

2- गत बैठक के प्रस्ताव संख्या 10 पुष्ट संख्या 18 कवे संवेध में विभिन्न न्यायालयों के आवेशों से जिन न्यायप्रकारियों को पूर्व में प्राप्त/प्राधिकरण द्वारा भूखण्ड आवंटन किया गये थे परन्तु कब्जा सुपूर्द नहीं किया गया, उन्हें कब्जा सुपूर्द करने एवं यदि कब्जा सुपूर्द करना संभव नहीं हो तो अन्य स्थान पर वैकल्पिक भूखण्ड उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में विचार विमर्श किया गया था। बैठक में प्रभारी अधिकारी विधि शाखा द्वारा ऐसे 21 प्रकरण प्रस्तुत किये गये, जिनका निम्न न्यास की बैठक दिनांक 1 फरवरी, 2007 के प्रस्ताव संख्या 6- कीर्तिनगर योजना सेक्टर बी को ड्रॉ कर अन्यत्र वैकल्पिक आवंटन करने के निर्णय को भी प्रस्तुत किया गया था।

गत बैठक में यह निर्णय किया गया था कि भूखण्ड एकसर्वेजक अधिकार प्राधिकरण में निहित है। अतः प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किये जायें।

प्रभारी अधिकारी विधि शाखा द्वारा प्रस्तुत 21 प्रकरणों में से 12 प्रकरण कीर्तिनगर सेक्टर बी के एवं 9 प्रकरण अन्य हैं। हाल ही में प्राधिकरण द्वारा जिला उपभोक्ता संरक्षण मंच में निर्धारित फॉर्म संख्या जी-21 पूर्वी पाल रोड योजना में सीकें पर मुद्राम लगाकर प्राची को भूखण्ड भूखण्ड का कब्जा प्रस्तावित किया है एवं तदनुसार ही न्यायालय में प्रार्थना पेश की गई है।

यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण का प्रथम प्रयास मूल भूखण्ड का कब्जा दिलवाना होना चाहिए। मुक्ति कीर्तिनगर सेक्टर बी के संबंध में तत्कालीन न्यास द्वारा मुसनी आवेशी भूमि को न्यास योजना में मूलतः समाहित किये जाने के प्रकरण सेक्टर-बी का भी नोटिफिकेशन करने का प्रस्ताव फास्ट किया गया है, कीर्तिनगर सेक्टर बी के 12 प्रकरण संबंधित जोधपुर विकास प्राधिकरण आवक कर नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्राधिकरण की आगामी बैठक में रखेंगे। कीर्तिनगर सेक्टर-बी के अतिरिक्त रोड 9 प्रकरण में सीकें पर अतिक्रमण हटाकर प्राचीय न्यायालयों के निर्णय अनुसार मूल भूखण्ड का ही कब्जा

दिलवाने का पत्रास किया जाये। यदि मूल भूखण्ड पर कब्जा देना समद नहीं है तो अन्यत्र भूखण्ड मिले जाने पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव संख्या 2
1- 100.00 करोड रुपये के ऋण के संबंध में
2- 20.00 करोड रुपये की लिमिट लेने हेतु।

1- बैठक में प्राधिकरण की आर्थिक स्थिति पर चर्चा की गयी। सचिव ने जानकारी दी कि प्राधिकरण की बैठक दिनांक 13 जनवरी, 2009 के प्रस्ताव संख्या 12 (8) के संदर्भ में अध्यक्ष महोदय का अर्द्धशारदात्मक पत्र क्रमांक 5 दिनांक 14 जनवरी, 2009 से राज्य सरकार से 100.00 करोड रुपये के ब्यालिंग फण्ड या अनुदान हेतु अनुरोध किया गया था। राज्य सरकार ने इस संबंध में 100.00 करोड रुपये ऋण के प्रस्ताव भिजवाने हेतु प्राधिकरण को लिखा। प्राधिकरण कार्यालय स्तर से 100.00 करोड रुपये के ऋण के प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किया गया है। जो राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है।

2- प्राधिकरण की तात्कालिक वित्तीय समस्या के समाधान हेतु इस प्रस्ताव पर विचार किया गया कि 20.00 करोड रुपये के ओवरड्राफ्ट की सुविधा ली जाये। यह ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्राधिकरण के लिए सहायक मिलने वाली सुविधा होगी जिस पर आवश्यकतानुसार राशि निकाली जा सकेगी साथ ही राशि की उपलब्धता होने पर इसी खाते में राशि जमा होती रहेगी जिससे प्राधिकरण पर ब्याज का भार नहीं पड़ेगा।

विभिन्न बैंकों से ओवरड्राफ्ट प्राप्त करने के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त किये गये। एचडीएफएफसी0 बैंक, बैंक ऑफ राजस्थान, यूको बैंक व बैंक ऑफ बड़ोदा के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। जो इस कार्यवाही के परिशिष्ट-2 पर सलगन हैं। चूंकि प्राधिकरण अधिनियम की धारा 57 के अनुसार राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त करके ही ऋण अथवा क्रेडिट लिमिट प्राप्त की जा सकती है। जातः सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार को 20.00 करोड रुपये के ओवरड्राफ्ट की स्वीकृति एवं गारण्टी पदान करने हेतु पत्र भिजवाया जावे साथ ही 100.00 करोड रुपये ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति हेतु भी अनुरोध किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 3 नीलामी बोलियों का अनुमोदन

प्रभाषी अधिकारी, नीलामी ने जानकारी दी कि पिछली कार्यकारी समिति की बैठक से अंज की बैठक के मध्य निम्नलिखित सूची में अंकित अनुसार नीलामी की गयी है एवं इन भूखण्डों की 1/4 राशि जमा है तथा शेष 3/4 राशि अनुमोदन के पश्चात् प्राप्त की जानी है। नीलामी की दर डी0एल0सी0 दर आरंभित दर से अधिक है एवं प्रचलित बाजार दरों के अनुरूप है।

क्र. सं.	बोलियों का नाम	नीलामी दिनांक	विस्तार	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल वर्गमीटर	बर्तमान उच्चतम दर	पूर्व दर	कुल कीलामी राशि
1	भारतीय लेबर-4 इ. शारदीय	5 Nov. 2007	आवसायिक भूखण्ड	66	83-61	53,100/- Sq. Mtr	--	44,37,691.00
2	सरकारी भवन संकर सी	19 Feb. 2009	राजकीय भूखण्ड	859	65-06	3,010/- Sq. Mtr	--	3,32,460.00
3	घरवा संख्या 778/1 बाण गंगा सुरभाण्ड रोड	20 Feb. 2009	खनसामिक भूखण्ड	38	49-31	21,000/- Sq. Mtr	7150/- Sq. Mtr	10,43,530.00
4	घरवा संख्या 778/1 8F1 गंगा सुरभाण्ड रोड	20 Feb. 2009	आवसायिक भूखण्ड	39	80-12	18,000/- Sq. Mtr	7150/- Sq. Mtr	14,42,160.00
5	सरकारी भवन	21	आवसायिक इ.	116	74-32	20,500/-	22,600/-	15,23,560.00

De

	दिनांक/दिन श्रावण	March, 2009				Sq. Mtr	Sq. Mtr	
6	कीर्तिनगर सेक्टर सी	25 March, 2009	सुवर्ण	31	250- 00	6500/- Sq. Mtr	--	16,25,000.00
7	कीर्तिनगर सेक्टर सी	25 March, 2009	सुवर्ण	32	250- 00	6700/- Sq. Mtr	--	16,75,000.00
8	कीर्तिनगर सेक्टर सी	25 March, 2009	सुवर्ण	35	83-61	5300/- Sq. Mtr	--	4,43,133.00
9	कीर्तिनगर सेक्टर सी	25 March, 2009	सुवर्ण	245	83.61	5721/- Sq. Mtr	--	4,44,889.00
10	गण अवलोकन प्रसाद सागरिका सेक्टर ए	26 March, 2009	सुवर्ण	127	203.50	2810/- Sq. Mtr	2900/- Sq. Mtr - 20%	5,72,004.00
11	गण अवलोकन प्रसाद सागरिका सेक्टर ए	26 March, 2009	सुवर्ण	128	242.60	2780/- Sq. Mtr	2900/- Sq. Mtr - 20%	6,74,528.00
12	गण अवलोकन प्रसाद सागरिका सेक्टर ए	31 March, 2009	सुवर्ण	37	167- 22	3600/- Sq. Mtr	3225/- Sq. Mtr - 20%	6,01,992.00

बैंक में वाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से कीर्तिनगर सेक्टर सी योजना में दिनांक 25 मार्च 2009 को भूखण्ड संख्या 248 क्षेत्रफल 63.61 वर्ग मीटर जिसकी उच्चतम बोली रुपये 4725/- प्रति वर्ग मीटर की दर से प्राप्त हुई, जिसे जिला कलक्टर प्रतिनिधि ने उक्त दर को अन्य भूखण्ड की तुलना में कम दर मानी है इसलिए उक्त भूखण्ड की नीलामी निरस्त करने का निर्णय लिया जाकर क्षमा 1/4 राशे लौटाने का निर्णय लिया गया तथा शेष बोली स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

संगति ने यह भी निर्णय पारित किया कि नीलामी बोली अनुमोदन हेतु संगति के समक्ष प्रस्तुत होने पर राशे प्राप्त हस्त में विलम्ब होता है। अतः जो नीलामी बोली डी0एल0सी0 दर एवं आरक्षित दर से अधिक है, उन बोलियों को स्वीकृत करने के अधिकार The Rajasthan Improvement Trust (Disposal of Urban Land) Rules, 1974 के नियम 17 एवं एनेक्सचर-ए की शक्तियाँ जो अध्यक्ष, न्यास में निहित हैं; ये शक्तियाँ आयुक्त, प्राधिकरण को प्रत्यायोजित करने का निर्णय लिया जाता है। आयुक्त, प्राधिकरण अपने स्तर पर नीलामी बोलियाँ स्वीकृत करने के लिए अधिकृत होंगे।

प्रस्ताव संख्या 4 प्राधिकरण के जोन का निर्धारण।

प्राधिकरण के कीर्तिनगर क्षेत्र में कृषि के साथ ही 4 जोन का मूठन प्रस्तावित किया गया था। इन जोन के बीच में कार्य का विभाजन विधा जाता है। अतः पूर्व में प्रस्तावित विभाजित 4 जोन में कार्य का विभाजन का प्रस्ताव संगति के समक्ष विचारार्थ रखा गया।

कार्य में द्वारा प्रस्तावित नियम, शर्तों वाली नियमन, योजना एवं अनेक निर्माण/अतिक्रमण इत्यादि के प्रस्ताव संगति में विचारार्थ रखे गये। संगति ने विचार विमर्श कर कार्य विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया कि प्रत्येक जोन में उपायुक्त (जोनल अधिकारी) को द्वारा 90 की, कम्पैनी तर्ती नियमन, योजना एवं अनेक निर्माण/अतिक्रमण

हटाने के कार्य के लिए अधिकतर होंगे। अवैध निर्माण/अतिक्रमण हटाने आदि से संबंधित कार्य प्राधिकरण अधिनियम की धारा 34 से 35 के अन्तर्गत है, की शक्तियां भी उपायुक्त (जोमल अधिकारी) में निहित होंगी। उपायुक्त अपने अधीनस्थ अथवा अन्य अधिकारी को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने, अतिक्रमण हटवाने की कार्यवाही आदि हेतु निर्देश दे सकेंगे।

प्रस्ताव संख्या 5 :: वाम्बे योजना एवं अन्य योजनाओं में 90 दिवस पश्चात् राशि जमा कराने हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों का नियमितकरण

वाम्बे योजना में जिन आवेदक द्वारा आवंटन के पश्चात् निर्धारित 90 दिवस की अवधि में राशि जमा नहीं करायी है उन आवेदकों के प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया है कि उनकी बकाया राशि एव शास्ती जमा कर नियमन किया जावे। जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	आवंटित आवेदन संख्या	योजना का नाम	आवंटन तिथि	आवंटन पत्र जारी करने की तिथि	प्रार्थी द्वारा नियमन कराने हेतु आवेदन की दिनांक	आवंटन-पत्र जारी से देरी की अवधि	विवेक विवरण
1	दीपक जी जगदीश पति श्री ललितराज	ए-66	वाम्बे योजना	25-1-06	2-5-06	27-2-09	9 माह	
2	दीपक जी शारदा पति श्री प्रदुप कुमार	ए-67	वाम्बे योजना	25-1-06	13-5-08	26-3-09	10 माह	
3	श्रीमती शोभा देवी पति श्री मुलायचन्द आवेदक पत्नी श्री भूलाय चन्द अपने माता के मृत्यु का प्रमाण-पत्र धरम का अर्थात् नाम अतिक्रमण हटाने के लिए जमा कराने की मांग की है।	सी-11	वाम्बे योजना शोला	25-4-06	10-4-07	17-2-09	11 माह	

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त आवेदकों को जिन्हें 90 दिवस से अधिक किन्तु एक वर्ष से कम का समय हुआ है एवं कार्यकारी समिति के क्षेत्र अधिकार में है इसलिए उपरोक्त आवंटियों को नियमन की स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 6 :: नीलागी योजना में 90 दिवस पश्चात् प्राप्त राशि जमा कराने के आवेदन-पत्रों पर विचार विमर्श।

नीलागी में निकल किये गये भूखण्डों में नीलागी स्वीकृति के 30 दिन के अन्दर सम्पन्न राशि जमा कराना होता है। यदि एक माह में राशि जमा नहीं हुई तो 90 दिवस

2

में ब्याज सहित जमा करायी जा सकती है इसके पश्चात् The Rajasthan Improvement Trust (Disposal of Urban Land) Rules, 1974 के नियम एनैक्साचर-ए के अनुसार 90 दिवस से एक वर्ष की अवधि में ब्याज एवं शारिती सहित सहित नियमन किया जा सकता है। चूंकि योलीदाता द्वारा 90 दिवस में राशि जमा नहीं करायी है तथा एक वर्ष से कम समय हुआ है इसलिए निम्नलिखित प्रकरणों में ब्याज एवं शारिती सहित राशि जमा कराने की स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रकरण समिति को सूक्ष्म प्रस्तुत किये गये-

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	नौलामी की तिथि	नौलामी स्वीकृति की तिथि	प्राप्ति द्वारा नियमन कराने हेतु आवेदन की दिनांक	नौलामी स्वीकृति से देरी की अवधि	विशेष विवरण
1-	श्री उम्मेदाराम बैनीवाल	1 (ब्य0)	विजय राजे नगर	13-8-08	25-8-08	2-3-98	6 माह 9 दिन	
2-	श्री नरेश सोलंकी	259	परिवहन नगर आणवदा अटो	22-10-08	12-11-08	16-3-09	4 माह	
3-	श्री गणेश राम पालीवाल	5 (ब्य0)	विजय राजे नगर	18-9-08	11-10-08	17-3-08	8 माह	

वाद विचार विमर्श सर्व समिति से बकाया राशि ब्याज एवं शारिती के साथ जमा कराई जाकर भूखण्ड नियमित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 7 : क्वालिटी कण्ट्रोल लेब की स्थापना एवं थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन के संबंध में विचार विमर्श।

वाद विचार विमर्श समिति ने निर्णय लिया कि वर्तमान में आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने पर इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर निर्णय नहीं लिया जा सकता है। अतः आचार संहिता समाप्त होने पर आयोजित होने वाली समिति की आगामी बैठक में प्रकरण निणयार्थ प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 8 : मेसर्स गेशन्हा एडवर्टाइजमेन्ट कम्पनी को बीओटीओ आधार पर यूनिपोल की स्वीकृति के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा पारित नवीनतम आदेश पर विचार विमर्श।

वाद विचार विमर्श समिति ने निर्णय लिया कि वर्तमान में आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने पर इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर निर्णय नहीं लिया जा सकता है। अतः आचार संहिता समाप्त होने पर आयोजित होने वाली समिति की आगामी बैठक में प्रकरण निणयार्थ प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 9 : गुमशुदा पत्रावली के संबंध में
1- राजबाग
2- उपभोक्ता भव

नगर विकास न्याय, जोधपुर के राग्य कार्यालय पत्रावलियों पर पत्रावली संख्या अंकित करने तथा रजिस्टर संधारण करने की प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी थी। इस कारण पत्रावलियों के गुम होने के प्रकरण सामने आ रहे हैं। आवेदक द्वारा पत्रावली के संबंध कार्यवाही वास्तु प्राथमिक पत्र पुरस्तुत करने पर ऐसे प्रकरण सामने आते हैं जिनमें पत्रावली

22

गुम हो चुकी होती है। इन प्रकरणों के निरतारण हेतु पत्रावलियों के पुनः बनाये जाने की आवश्यकता रहती है। अतः सदस्यों द्वारा डुप्लीकेट पत्रावलियों के संबंध में निम्न अनुसार सुझाव दिये:-

- 1- पत्रावली खोलने से पहले सर्व नोट जारी किया जावे।
- 2- अखबार में विज्ञापित जारी की जावे कि वह पत्रावली बनाई जा रही है किसी को कोई आपत्ति होती प्रस्तुत करें तथा लापरवाही के लिए जिम्मेदारी तय करने हेतु प्रथम सूचना दर्ज करवायी जावेगी।
- 3- प्रत्येक कर्मचारी की शाखा में तैनातगी अवधि का विवरण स्थापन शाखा में संधारित किया जावे।
- 4- जांच अधिकारी नियुक्त कर जिम्मेदारी तय की जावे।

बिन्दु संख्या 1 से 4 की पालना होने पर डुप्लीकेट पत्रावली बनाने हेतु दस्तावेज संकलित कर कार्यकारी समिति के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जावे। कार्यकारी समिति गुणावगुण के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने पर विचार करेगी।

समिति ने बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त सुझावों पर विचार कर निर्णय लिया कि उपरोक्तानुसार अंकित प्रक्रिया के अनुसार डुप्लीकेट पत्रावली तैयार कर निर्णय हेतु कार्यकारी समिति के समक्ष रखी जावे।

प्रस्ताव संख्या 10 :: अतिक्रमण निरोधक दल को शक्तियां प्रदान करने के संबंध में।

समिति ने बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया कि प्राधिकरण अधिनियम की धारा 31 से 35 तक की शक्तियां उपायुक्त को प्रदत्त करने हेतु उपरोक्त प्रस्ताव संख्या 4 में निर्णय लिया जा चुका है। अतः तदनुसार कार्यवाही की जावे।

प्रस्ताव संख्या 10 :: अधिकारियों को दूरभाष की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में।

बाद विचार विमर्श समिति ने निर्णय लिया कि वर्तमान में आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने पर इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर निर्णय नहीं लिया जा सकता है। अतः आचार संहिता समाप्त होने पर आयोजित होने वाली समिति की आगामी बैठक में प्रकरण निणयार्थ प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 10 :: आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2009-10 एवं संशोधित अनुमान वर्ष 2008-09

यह प्रस्ताव प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार का है इसलिए कार्यकारी समिति इसका अनुमोदन नहीं कर सकती है। चूंकि यह तात्कालिक प्रकृति का कार्य है इसलिए जरिये परिषदने प्रस्ताव प्राधिकरण से पारित करवाया जावे।

रात्रिपश्चात् बैठक राधन्ध्याद समाप्त हुई।

(रमेशचन्द्र गुप्ता)

साथीय

जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

क्र.मांक / बैचक / 2009 / जो. वि. प्र. आ. आ. 968-93 दिनांक : 30 अप्रैल, 2009

(968-93)

तेलिफि-

7
4/5/09

- 01. निजी सहायक (अध्यक्ष महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
- 02. प्रमुख शासन सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 03. जिला कलेक्टर महोदय, जोधपुर
- 04. जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, जोधपुर
- 05. निजी सहायक (आयुक्त महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
- 06. आयुक्त (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) नगर निगम, जोधपुर
- 07. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
- 08. मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
- 09. प्रबन्धक, निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
- 10. प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड, जयपुर
- 11. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर
- 12. उप निदेशक, पर्यटन, जोधपुर
- 13. प्रशासकीय अधिकारी

14 - प्रशासकीय अधिकारी LAC (रमेशचन्द्र गुप्ता) 20

15 - सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर

17 - प्रशासकीय अधिकारी

18 - सचिव

19 - निदेशक, वि. वि. राज्य

20 - सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण

21 - प्रशासकीय अधिकारी

22 - प्रशासकीय अधिकारी

23 - प्रशासकीय अधिकारी

24 - प्रशासकीय अधिकारी

25 - प्रशासकीय अधिकारी

26 - प्रशासकीय अधिकारी

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की कार्यकारी समिति की श्री गौरव गोयल, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में आयोजित द्वितीय बैठक दिनांक 17 अप्रैल, 2009 में उपस्थित सदस्यों/ अन्य अधिकारियों का विवरण

सदस्यगण:-

01. श्री वंशीलाल भाटी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जोधपुर
02. श्री अनिल पालीवाल, आयुक्त, नगर निगम, जोधपुर
03. श्री सुन्दरलाल बी. माथुर, अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर प्रतिनिधि अति. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
04. श्री मोहम्मद उमर, अधीक्षण अभियन्ता, (शहर वृत) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर प्रतिनिधि मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
05. श्री एस के. कुलश्रेष्ठ, जॉनल चीफ इंजिनियर, डिस्कॉम, जोधपुर प्रतिनिधि प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
06. श्री मनोज चौधरी, वृत्ताधिकारी (केन्द्रीय), जोधपुर प्रतिनिधि जिला पुलिस अधीक्षक (शहर) महोदय, जोधपुर
07. श्री भानुप्रताप, सहायक निदेशक, पर्यटन, जोधपुर
08. श्री वंशीलाल बजार, मुख्य प्रबन्धक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर प्रतिनिधि प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जयपुर
09. श्री खेताराम चौधरी, सहायक नगर नियोजक प्रतिनिधि वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर

अन्य अधिकारी:-

10. श्री रमेशचन्द्र गुप्ता, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण,
11. श्री विनोद विरगानी, अति. मुख्य अभियन्ता, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
12. श्री राजेन्द्रसिंह राटौड़, विशेषाधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13. श्री अनवर अली खान, विशेषाधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. श्री खान मोहम्मद खान, भूमि अवाप्ति अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. श्री अनिल माथुर, उप नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. श्री अरुण मेहता, अधिशासी अभियन्ता-शहर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17. श्री निरंजन माथुर, अधिशासी अभियन्ता-सूरसागर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
18. श्री निहाल सिंह, लेखाधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
19. श्री गौरवसिंह भाटी, तहसीलदार, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर